Influence of Demonetization on Indian Economy

(भारतीय अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण का प्रभाव)

Mr. Dinesh Kumar Patidar
Assistant Professor, Economics,
Government College Suwasra, Mandsaur (M.P.), India
Corresponding Author: Patidardinesh886@gmail.com

DOI: 10.52984/ijomrc2106

ABSTRACT

आर्थिक प्रचलन से धन की इकाइयों अर्थात रुपयें के प्रचलित स्वरूप को वापस लेना ही विमुद्रीकरण है। पैसे की इकाइयों को कानूनी निविदा की स्थिति से वंचित कर दिया जाता है। विमुद्रीकरण को एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसके द्वारा मुद्रा इकाइयाँ वैध मुद्रा नहीं रहती। करेंसी नोटों को वैध मुद्रा के रूप में नहीं लिया जाना ही विमुद्रीकारण है। विमुद्रीकरण सरकार द्वारा उठाया गया एक ऐसा कदम है जहां मुद्रा इकाइयां कानूनी निविदा के रूप में अपनी स्थिति को समाप्त कर देती हैं। राष्ट्रीय मुद्रा को बदलने के लिए विमुद्रीकरण एक बुनियादी शर्त है। दूसरे शब्दों में, विमुद्रीकरण को मुद्रा का परिवर्तन कहा जा सकता है जहाँ मुद्रा की नई इकाइयाँ पुरानी को बदल देती हैं। इसमें एक ही मूल्य वर्ग के नए नोट या सिक्के या पूरी तरह से नए मूल्यवर्ग का परिचय शामिल हो सकता है। भारत में तीन बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया जा चुका है। पहला विमुद्रीकरण 12 जनवरी 1946 (शनिवार) को, दूसरा 16 जनवरी 1978 (सोमवार) को और तीसरा 8 नवंबर 2016 (मंगलवार) को हुआ था। अध्ययन विमुद्रीकरण के अर्थ और कारणों, विमुद्रीकरण के क्षेत्र–वार प्रभाव को समझने का प्रयास करता है। यह अध्ययन भारतीय अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों की भी जानकारी देता है। यह शोध–पत्र वर्णनात्मक प्रकृति का है इसलिए सभी आवश्यक और प्रासंगिक डेटा विभिन्न पत्रिकाओं, पत्रिकाओं से प्रकाशित पत्रों और वेबसाइटों के लिए लिया गया है। आवश्यकतानुसार विषय पर सैद्धांतिक जानकारी के लिए पुस्तकों को भी संदर्भित किया गया है।

Keywords: मुद्रा, विमुद्रीकरण, डिजिटल, अर्थव्यवस्था।

परिचय

विमुद्रीकरण का अर्थ है मुद्रा के किसी भी मूल्यवर्ग के कानूनी निविदा अधिकारों को वापस लेना, अर्थात् धन की इकाइयों का कानूनी निविदा की स्थिति से वंचित कर दिया जाना है। विमुद्रीकरण किसी भी मुद्रा के कानूनी निविदा अधिकारों को छीनने का एक कार्य है। मुद्रा की इकाइयों को वैध मुद्रा नहीं माना जाना। विमुद्रीकरण कानूनी निविदा के रूप में अपनी स्थिति की धन की एक इकाई को बंद करने की प्रक्रिया है। मुद्रा की नई इकाइयों के साथ पुरानी मुद्रा को बदलने के लिए विमुद्रीकरण एक आवश्यक शर्त है... इसमें एक ही मूल्यवर्ग या पूरी तरह से नए मूल्यवर्ग के नए नोट या सिक्के शामिल हो सकते हैं। भारत में तीन बार मुद्रा का विमुद्रीकरण किया जा चुका है। पहला विमुद्रीकरण **12 जनवरी 1946** (शनिवार) को, दूसरा **16 जनवरी 1978** (सोमवार) को और तीसरा **8 नवंबर 2016** (मंगलवार) को हुआ था। सरकार का मानना है कि यह मुद्रा प्रतिबंध चार मुख्य कारणों से जरूरी है। महंगाई पर नियंत्रण, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई, जाली नोटों को हटाना और नकद लेन–देन को हतोत्साहित करना। भारत जैसे विकासशील देश को देश की भलाई के लिए इस तरह की समस्याओं से बाहर निकलने का समाधान खोजना होगा। सरकार को इस निर्णय को गुप्त रखने की आवश्यकता थी ताकि नोटबंदी की घोषणा से पहले कर चोरों को इस सफाई मिशन के बारे में पता न चले

साहित्य की समीक्षाः

शानभोग गिरीश, कुमार, ए. प्रशांत, भट, स्वाति और शेट्टीगर, चेतन (2016) ने मुद्रा प्रतिबंध को आतंकवाद के वित्तपोषण के लिए कथित रूप से इस्तेमाल किए गए जाली बैंक नोटों को रोकने के साथ–साथ देश में काले धन और भ्रष्टाचार के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में परिभाषित किया। विमुद्रीकरण से देश में नकदी की कमी हो जाती है जो कई छोटे व्यवसायों, कृषि और परिवहन के लिए हानिकारक साबित होती है। नकदी की कमी के कारण अफरा–तफरी मच गई और देश भर में बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतारों के कारण अधिकांश लोगों को अपने नोट बदलने में समस्या का सामना करना पड़ा। यह विमुद्रीकरण कदम भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में काले धन और भ्रष्टाचार पर सबसे बड़ा हमला और डिजिटलीकरण की ओर एक आंदोलन साबित हुआ। यह

डिजिटल भुगतान को भी प्रोत्साहित करता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि विमुद्रीकरण लघु, मध्यम और दीर्घावधि में फायदेमंद है।

मुथुलक्ष्मी, ई. कामाची (2017) ने **भारतीय अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण के प्रभाव– मुद्दे और चुनौतिया**ं शीर्षक वाले अपने पेपर में कहा है कि जब अर्थव्यवस्था से पैसा वापस ले लिया जाता है, तो देश को अल्पावधि में लाभ नहीं होगा। दूसरी ओर, यदि पैसा अर्थव्यवस्था में प्रवेश करता है तो इसका सकारात्मक और सार्थक प्रभाव होगा। वह यह भी कहती हैं कि विमुद्रीकरण का कदम, एक तरफ, काले धन, भ्रष्टाचार, हवाला लेनदेन, नकली मुद्रा और आतंकवाद के वित्तपोषण पर एक गंभीर हमला था। दूसरी ओर, कमोडिटी और रियल एस्टेट जैसे विभिन्न क्षेत्रों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा।

शाह, अयाश युसूफ (2017) ने कहा कि नोटबंदी भ्रष्टाचार, काले धन और टेरर फंडिंग के खिलाफ लड़ाई में प्रमुख कदमों में से एक है। हालांकि, यह निर्णय बिना उचित तैयारी के लिया गया और इसका जनता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। पर्याप्त नए करेंसी नोटों को छापे बिना 86 प्रतिशत करेंसी नोटों को बाजार के सभी लेन–देनों को पछाड़ते हुए वापस ले लिया गया। सिर्फ आम लोगों को नोट बदलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा, न कि टारगेट किए गए लोगों को। देश को काले धन से मुक्त करने और टैक्स डिफॉल्टरों और काला धन रखने वालों को बाहर निकालने के इरादे से सरकार ने 500 और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने का कदम उठाया है। विमुद्रीकरण की अचानक घोषणा और ठीक से योजना बनाने में विफल रहने से आम जनता में अफरातफरी मच गई है। आम लोगों को बिना पैसे के खरीदारी करने में परेशानी हो रही है, अंतहीन कतारों में अपना समय बर्बाद करने से अग्रिम योजना से आसानी से बचा जा सकता था।

वीरकुमार, के. (2017) का मानना है कि सरकार द्वारा 500 और 1000 के नोटों के विमुद्रीकरण की घोषणा भारत के नागरिक के लिए एक बड़ा झटका है। कर चोरी, जाली मुद्रा और आतंकी गतिविधियों के वित्तपोषण की समस्या का मुकाबला करने के लिए अर्थव्यवस्था से उच्चतम मुद्रा नोट वापस ले लिए जाते हैं। यह दिखाया गया है कि बैंक खातों में भारी धन जमा किया जा रहा है जो निर्दिष्ट सीमा से अधिक हैं और दंड और करों के अधीन हैं। ई–वॉलेट, डेबिट और क्रेडिट कार्ड के उपयोग में

जबरदस्त वृद्धि हुई है और इससे बेहतर कैशलेस इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होगा।

अभानी धारा के. (2017) का मानना है कि यह विमुद्रीकरण पिछले दो की तुलना में अधिक सफल साबित हो रहा है। जमाना बदल रहा है। लोग भुगतान के तरीके के रूप में ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग कर रहे हैं। नोटबंदी को सफल बनाने के लिए बैंक कर्मचारी अपना सर्वश्रेष्ठ दे रहे हैं। उनका समर्थन बहुत मायने रखता है। हालांकि विमुद्रीकरण का कदम अर्थव्यवस्था में कुल काले धन को हथियाने में विफल रहा है, लेकिन इसने कम से कम काला धन रखने वाले लोगों के मन में डर पैदा कर दिया है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि काले धन, आतंकवाद और भ्रष्टाचार आदि की समस्या से निपटने के लिए विमुद्रीकरण एक अनिवार्य कदम था।

शुक्ला, बाल गोविंद और गुप्ता, हरिओम (2018) ने अपने पेपर में भारत में विमुद्रीकरण पर व्यावसायिक छात्रों के परिप्रेक्ष्य का एक अन्वेषणात्मक अध्ययन में उन्होंने अपने अध्ययन के लिए प्राथमिक डेटा का इस्तेमाल किया और निष्कर्ष निकाला कि लोग सरकार द्वारा की गई किसी भी पहल का सक्रिय रूप से समर्थन करते हैं, जो मूल रूप से भ्रष्टाचार, काले धन और देश में आतंकवाद और नक्सलवाद जैसे किसी भी अन्य खतरे को खत्म करने के लिए लक्षित हैं।

अनुसंधान विधिः

यह अध्ययन वर्णनात्मक प्रकृति का है और विमुद्रीकरण के अर्थ और कारणों के साथ–साथ विमुद्रीकरण के क्षेत्र–वार प्रभाव और भारतीय अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों के बारे में बताता है। इसलिए द्वितीयक डेटा का उपयोग करता है। संपूर्ण अध्ययन केवल अवलोकन और दस्तावेजी विश्लेषण पर आधारित है। इसके अलावा, आवश्यक और प्रासंगिक माध्यमिक डेटा विभिन्न शोध पत्रों, पत्रिकाओं और प्रकाशनों, वेबसाइटों और कई अन्य से एकत्र किए जाते हैं। आवश्यकतानुसार विषय पर सैद्धांतिक जानकारी के लिए पुस्तकों को भी संदर्भित किया गया है

अध्ययन का उद्देश्यः

1. विमुद्रीकरण के अर्थ और कारणों को समझना।
2. विमुद्रीकरण के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का अध्ययन करना।
3. विमुद्रीकरण के क्षेत्रवार प्रभाव का अध्ययन करना।

प्राप्तियॉः

इस भाग को निम्नलिखित उप भागों में विभाजित किया गया है,

- **विमुद्रीकरण के कारण।**
- **भारतीय अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव।**

विमुद्रीकरण के कारण

1. **काला धनः** विमुद्रीकरण भारत सरकार द्वारा काले धन पर अंकुश लगाने के लिए की गई एक साहसिक और क्रांतिकारी कार्रवाई थी और इसका देश में समानांतर अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ेगा। इस कदम से जेब और काले धन वाले लोगों की पहचान की जा सकती है। कुछ व्यवसाय जैसे संपत्ति डीलर, जौहरी, विदेशी मुद्रा डीलर, निजी साहूकार आमतौर पर मुद्रा नोटों के रूप में बड़ी मात्रा में बेहिसाब धन रखते हैं। इस तरह के बेहिसाब धन ने देश में एक समानांतर अर्थव्यवस्था का निर्माण किया था। इस तरह का अवैध पैसा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष माध्यमों से बैंक खातों में पहुंचा है।
2. **नकली करेंसी रैकेट पर लगामः**नोटबंदी से नकली नोटों की बर्बादी हुई है। अर्थव्यवस्था से उच्चतम मुद्रा नोटों को वापस लेने से नकली मुद्रा सिंडिकेट पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा, इस प्रकार जम्मू–कश्मीर, नक्सल प्रभावित राज्यों और उत्तर–पूर्वी राज्यों में आतंकी फंडिंग पर रोक लगेगी। जालसाजों के पास नकली मुद्रा को व्यर्थ छोड़ दिया गया है, और उच्च सुरक्षा के साथ नए मुद्रा नोटय नकली को असंभव बनाना। विमुद्रीकरण अर्थव्यवस्था में चल रही नकली मुद्रा पर एक सर्जिकल हमला था। विमुद्रीकरण ने उन नकली नोटों को केवल कागज के टुकड़े में बदल दिया है।
3. **ऑनलाइन लेनदेनः** विमुद्रीकरण का आदर्श वाक्य कैशलेस डिजिटल अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करना था। अधिक से अधिक नकद–रहित या कम–नकद लेनदेन से आय का अधिक प्रकटीकरण होगा जिससे प्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि होगी। नकद लेनदेन में कमी के साथ, भुगतान के वैकल्पिक रूपों की मांग अधिक होगी। भुगतान के

इलेक्ट्रॉनिक मोड जैसे ऑनलाइन लेनदेन, एप्लिकेशन के माध्यम से भुगतान, ई–वॉलेट ई–बैंकिंग, डेबिट और क्रेडिट कार्ड का उपयोग आदि निश्चित रूप से मांग में पर्याप्त वृद्धि देखेंगे माओवादियों को मारने के लिएरू इस कदम ने वास्तव में माओवादियों के साथ पैसा बेकार कर दिया। जैसा कि बताया गया है कि छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों ने अपने पास 7000 करोड़ रुपये से अधिक जमा कर रखे थे। ऐसी सभी मुद्रा अब कुछ नहीं बल्कि कागज के टुकड़े है।

4. **जीडीपी में वृद्धिः** हालांकि विमुद्रीकरण ने सामान्य रूप से अचल संपत्ति और संपत्ति, निर्माण और घरेलू खपत जैसे क्षेत्रों को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, यह माना जाता है कि जीडीपी वृद्धि के लिए दीर्घकालिक लाभ कम से अधिक होगां

विमुद्रीकरण का क्षेत्रवार प्रभावः

1. **अचल संपत्ति और संपत्तिः** यह क्षेत्र नोटबंदी से सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में से एक होगा। विमुद्रीकरण ने अधिकांश बिल्डरों के व्यवसाय को समाप्त कर दिया है क्योंकि उनके लेन–देन का एक बड़ा हिस्सा बैंकों के हस्तांतरण या चेक लेनदेन के बजाय नकदी पर निर्भर करता है। अन्य क्षेत्रों की तरह, इस क्षेत्र में भुगतान में नकद घटक की उच्च भागीदारी होने के कारण सीमांत बिल्डरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। असंगठित बिल्डर्स सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं। खरीदारों को आकर्षित करने के लिए, बिक्री में अप्रत्याशित गिरावट के कारण बिल्डरों को नकदी की कमी का सामना करना पड़ेगा, बिल्डरों को आकर्षक ऑफर और अन्य लाभ पेश करने होंगे। विमुद्रीकरण का पुनर्विक्रय और भूमि खंड पर सीधा प्रभाव पड़ेगा क्योंकि इन लेनदेन में नकदी एक प्रमुख भूमिका निभाती है। अधिकांश खाते में जमा नकदी को सिस्टम से विमुद्रीकरण द्वारा निकाला गया है।

2. **रत्न और आभूषणः** ग्राहकों द्वारा भुगतान के बड़े हिस्से में आभूषण खरीदने के लिए नकद शामिल होता है, इसलिए इस क्षेत्र में विमुद्रीकरण का प्रभाव काफी अधिक है। विमुद्रीकरण ने लोगों को अपनी दैनिक जरूरतों को पूरा करने के लिए कम नकद उपलब्ध कराया, आभूषण खरीदने की तो बात ही छोड़ दी। असंगठित क्षेत्र के छोटे खुदरा विक्रेता सबसे अधिक प्रभावित हुए जिससे आभूषणों की मांग में कमी आई। कई ज्वैलर्स ने प्रतिबंधित नोटों का लाभ उठाने के लिए अपने बाजार मूल्य से अधिक पर सोना बेचना शुरू कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप ऐसे ज्वैलर्स पर आयकर छापे पड़े। कई ज्वैलर्स को नोटिस भी जारी किया गया है। यह क्षेत्र विमुद्रीकरण से गंभीर रूप से प्रभावित है क्योंकि खरीदार नकद में भुगतान करना पसंद करते हैं।
3. **बैंकः** बैंक नोटबंदी की इस पूरी प्रक्रिया की रीढ़ साबित हुए हैं और सबसे बड़े लाभार्थी भी हैं। सरकार के निर्देशानुसार, पुराने नोटों को नए के साथ बदलना पड़ता है, इसके परिणामस्वरूप बैंकों की तरलता की स्थिति में वृद्धि हुई है जिसका उपयोग ऋण देने के लिए किया जा सकता है। कई बैंकों ने जमा और उधार दोनों दरों में कटौती की है।
4. **मीडिया और मनोरंजन उद्योगः** मुद्रा प्रतिबंध ने मीडिया और मनोरंजन उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव डाला क्योंकि इसके परिणामस्वरूप दर्शकों की संख्या कम हुई। गिरावट का बड़ा हिस्सा निम्न मध्यम वर्ग में देखा गया है। नोटबंदी के अचानक लिए गए फैसले का असर फिल्म इंडस्ट्री पर भी पड़ा। इससे फिल्मों का निर्माण ठप हो गया। साथ ही, उद्योग में नए और छोटे खिलाड़ी विमुद्रीकरण से सबसे अधिक प्रभावित हैं।

5. **आतिथ्य और पर्यटनः** विमुद्रीकरण के कारण भारतीय पर्यटन उद्योग बुरी तरह प्रभावित हुआ है क्योंकि अधिकांश खर्च नकद में है। काले धन से प्रायोजित ज्यादातर लग्जरी विदेश यात्राएं ठप हो गई हैं। नकदी की किल्लत से स्थानीय पर्यटन भी प्रभावित होगा असंगठित क्षेत्र सबसे अधिक नकदी में भुगतान करने में असमर्थता से प्रभावित है, इसके अलावा, नकदी की अक्षमता के साथ रेस्तरां के व्यवसायों को भी मंदी का सामना करना पड़ रहा है।
6. **विलासिता की वस्तुएंः** विमुद्रीकरण का इस क्षेत्र पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा। अधिकांश लोग अपना बेहिसाब पैसा विलासिता पर खर्च करते हैं। नोटबंदी के बाद लग्जरी सेगमेंट और इससे जुड़े बिजनेस जैसे कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक्स, लग्जरी कार को बड़ा झटका लगेगा।
7. **ऑटोमोबाइलः** विमुद्रीकरण ने ऑटोमोबाइल उद्योग को भी प्रभावित किया है चार पहिया लक्जरी कारों की तुलना में दोपहिया कारोबार में मांग में बड़ी गिरावट देखी गई है क्योंकि खरीदार दोपहिया वाहन खरीदने के लिए नकद भुगतान करना पसंद करते हैं। पुरानी कार उद्योग एक अन्य खंड है जो विमुद्रीकरण से प्रभावित है जिसमें कई डीलरों द्वारा बिक्री में अचानक कमी की सूचना दी गई है। इस उद्योग में,
8. **कृषिः** कृषि को प्रभावित करने वाले विभिन्न कारक हैं जैसे बिक्री, वितरण, विपणन और परिवहन, ऐसे कारक प्रमुख रूप से नकदी पर निर्भर हैं। इसके अलावा, विमुद्रीकरण ने आपूर्ति श्रृंखला को बाधित कर दिया, यह क्षेत्र खराब होने वाली वस्तुओं की भारी बर्बादी से बुरी तरह प्रभावित हुआ है। थोक केंद्रों, मंडियों और उपभोक्ताओं को दैनिक आधार पर अपने उत्पाद बेचने वाले छोटे किसान भी

विमुद्रीकरण से प्रभावित हुए हैं।

9. **श्रम प्रधान क्षेत्रः** दिहाड़ी मजदूरों को भुगतान करने के लिए भारी मात्रा में नकदी की आवश्यकता होती है, उन्हें अपना नियमित सामान खरीदने में समस्या का सामना करना पड़ता है। खनन, कपड़ा और चमड़ा उद्योगों में ठेका कर्मियों के साप्ताहिक भुगतान पर बैंक से निकासी की सीमा प्रभावित हो रही है। साथ ही नकद निकासी पर प्रतिबंध से फैक्ट्री मालिकों की दैनिक जरूरतें भी प्रभावित हो रही हैं। इससे इस क्षेत्र में खरीद और उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। हालांकि नकदी प्रवाह सामान्य होने के बाद स्थिति में सुधार होगा।

भारतीय अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण का प्रभावः

1. **सकारात्मक और नकारात्मक सकारात्मक काला धनः** प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके में काले धन को दबा दिया है। कुल 17 लाख करोड़ रुपये की मुद्रा में से 3 लाख करोड़ रुपये काले धन के रूप में होने का अनुमान है। काले धन के संचालक समानांतर अर्थव्यवस्था चलाते हैं जो देश की अर्थव्यवस्था के आधार को कमजोर करता है। मोदी के विमुद्रीकरण के फैसले के परिणामस्वरूप बैंक के पास भारी जमा राशि जमा हो गई, सभी बेहिसाब धन या तो भारी जुर्माना के साथ बैंकों में जमा कर दिया गया या बस नष्ट कर दिया गया।
2. **अर्थव्यवस्थाः** यह विमुद्रीकरण काले धन को साफ करके अर्थव्यवस्था के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ है, जिसने बदले में खजाने में अधिक उधार लिया है, मुद्रास्फीति के दृष्टिकोण में सुधार हुआ है और भारत की जीडीपी में वृद्धि हुई है। निवेश के अवसरों को भी पुनर्जीवित किया गया है और बुनियादी ढांचे और विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा दिया है। बैंकों में जमा की गई एक बड़ी राशि जिसने बदले में ब्याज दरों और कम आयकर दर को कम करने में मदद की।
3. **अचल संपत्तिः** ऐसा कहा जाता है कि अचल संपत्ति एक ऐसा उद्योग है जो काले धन पर फलता–फूलता है। इस क्षेत्र में शामिल अवैध धन

की राशि बहुत बड़ी है। एक अनुमान बताता है कि दिल्ली–एनसीआर में रियल एस्टेट के कम से कम 40 प्रतिशत सौदे काले रंग में होते हैं। मोदी के विमुद्रीकरण के कदम ने अचल संपत्ति क्षेत्र में बेहिसाब धन के प्रवाह को कम कर दिया। इससे रियल एस्टेट क्षेत्र में काले धन के उपयोग को कम करने में मदद मिलेगी जिसके परिणामस्वरूप भूमि और संपत्ति की कीमतों में कमी आएगी।

4. **हवाला लेन–देनः** हवाला कारोबारियों के लिए नोटबंदी एक बड़ा झटका था। हवाला में पैसे को उसके वास्तविक संचलन के बिना स्थानांतरित किया जाता है। हवाला मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग को आसान बनाने का जरिया बन गया था। हवाला रैकेट काले धन पर चलता है। अर्थव्यवस्था से काले धन की अचानक वापसी हवाला ऑपरेशन के लिए एक सर्जिकल स्ट्राइक थी। हवाला संचालकों द्वारा करेंसी नोटों को नष्ट करने की भी सूचना मिली है।

5. **जाली करेंसीः** नोटबंदी ने नकली भारतीय करेंसी को एक बड़ा झटका दिया। देश के अंदर और बाहर दोनों जगह काम कर रहे सिंडिकेट ऑपरेटर की मुद्रा बर्बाद हो गई है। नकली मुद्रा भारतीय मुद्रा के वास्तविक मूल्य के अवमूल्यन के पीछे मुख्य कारणों में से एक है। भारतीय सांख्यिकी संस्थान ने बताया कि किसी भी समय 400 करोड़ रुपये के नकली नोट अर्थव्यवस्था में प्रचलन में थे और हर साल लगभग 70 करोड़ रुपये के नकली नोट देश में धकेले जाते हैं। लेकिन वास्तविक संख्या इससे कहीं अधिक हो सकती है। प्रधान मंत्री मोदी के 500 और 1,000 रुपये के पुराने नोटों पर प्रतिबंध लगाने और उन्हें नए के साथ बदलने के निर्णय के साथ नकली मुद्रा का प्रचलन पूरी तरह से समाप्त हो गया। चूंकि नए करेंसी नोट अत्यधिक उन्नत सुरक्षा विशेषताओं के साथ आए हैं, जिन्हें दोहराना मुश्किल से संभव है।

चलनिधि संकटः विमुद्रीकरण ने तरलता की समस्या को जन्म दिया क्योंकि लोगों को अपनी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए पर्याप्त मात्रा में नकदी प्राप्त करना मुश्किल हो गया था। समाज का सीमांत वर्ग अपने दैनिक लेनदेन को पूरा करने के लिए मुख्य रूप से नकदी पर निर्भर करता है। प्रचलन में कुल मुद्रा में से 500

रुपये के नोट मूल्य के मामले में लगभग 49प्रतिशत थे। 500 रुपये के नोटों को फिर से आपूर्ति करने में जितना अधिक समय लगेगा, तरलता संकट की अवधि उतनी ही अधिक होगी।

कल्याण की हानिः निम्न मध्यम और निम्न वर्ग की अधिकांश आबादी अपने दैनिक लेनदेन को पूरा करने के लिए मुद्रा का उपयोग करती है। समाज के ऐसे वर्ग जैसे दिहाड़ी मजदूर, छोटे व्यापारी और समाज के अन्य सीमांत वर्ग नकदी का अधिक उपयोग करते हैं। नकदी के अभाव में समाज के इन वर्गों की आमदनी खत्म हो गई है। नकदी की कमी ने फर्मों को अपनी श्रम लागत में कटौती करने के लिए मजबूर किया और इस प्रकार निम्न मध्यम वर्ग की आय कम हो गई।

खपतः नकदी की कमी ने भारत में लोगों के उपभोग व्यवहार पर प्रतिकूल प्रभाव डाला। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं की बिक्री अल्पावधि में बाधित होने की संभावना है, विशेष रूप से असंगठित चौनलों के माध्यम से बिक्री नकद खरीद है। खुदरा विक्रेताओं द्वारा अधिकांश खरीद नकदी के माध्यम से होती है जिससे उनके व्यापार की मात्रा में कमी आई है।

सकल घरेलू उत्पाद में कमीः उच्चतम मुद्रा नोटों को वापस लेने से अर्थव्यवस्था की विकास दर कम हो जाती है। विमुद्रीकरण खपत पैटर्न, आय, निवेश आदि को कम करता है। इससे भारत की विकास दर में मंदी आ सकती है क्योंकि तरलता संकट तीन–चार महीने तक रह सकता है।

ब्याज दर और बैंक जमाः विमुद्रीकरण के कारण अल्पावधि में बैंक की जमा राशि बढ़ सकती है, लेकिन लंबी अवधि में कम हो जाएगी। लोगों द्वारा बैंक में जमा की गई इस तरह की तरल नकदी को यह नहीं

निष्कर्षः

सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को विमुद्रीकृत करने और इसे नए से बदलने के कदम ने देश को आश्चर्यचकित कर दिया है। यह कदम अवैध धन, भ्रष्टाचार, आतंकी फंडिंग और नकली मुद्रा के खतरे से निपटने का एक प्रयास था। पुरानी मुद्रा को विमुद्रीकृत करने के निर्णय को भारतीय अर्थव्यवस्था के इतिहास में अघोषित धन के खिलाफ एक सर्जिकल स्ट्राइक के रूप में माना जाता था, यह कैशलेस अर्थव्यवस्था की ओर एक कदम हो सकता है। विमुद्रीकरण के बाद देश में तरलता की कमी हो गई, देश भर के बैंकों और एटीएम को विभिन्न छोटे

व्यवसायों, कृषि और परिवहन पर हानिकारक प्रभावों के साथ गंभीर नकदी की कमी का सामना करना पड़ा। भारत सरकार द्वारा मुद्रा प्रतिबंध ने अल्पावधि में अराजकता पैदा कर दी क्योंकि पुराने नोटों वाले अधिकांश लोगों को पूरे भारत में बैंकों और एटीएम के बाहर लंबी कतारों में उन्हें बदलने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। प्रचलन में पुराने करेंसी नोटों का कुल मूल्य 14.2 ट्रिलियन रुपये था, जो प्रचलन में कुल मूल्य का लगभग 86प्रतिशत है। काला धन या तो भारी करों और जुर्माने का भुगतान करके या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष चौनलों के माध्यम से बैंक खातों में पहुंचा है। विमुद्रीकरण भारतीय अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव लाएगा क्योंकि यह ई–वॉलेट और ऐप जैसे भुगतान के डिजिटल मोड को प्रोत्साहित करता है, ई–बैंकिंग का उपयोग करके ऑनलाइन लेनदेन, प्लास्टिक मनी का उपयोग आदि विमुद्रीकरण मध्यम से लंबी अवधि में अर्थव्यवस्था के लिए फायदेमंद है।

संदर्भः

1. अभानी, डी.के. (2017): **वेरावल सिटी के संदर्भ में बैंकिंग क्षेत्र पर विमुद्रीकरण के प्रभाव पर एक अध्ययन**, विपणन और वित्तीय प्रबंधन के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल, 5(3), 21–26।
2. शुक्ला, बी.जी. और गुप्ता, एच, (2018): **भारत में विमुद्रीकरण पर व्यावसायिक छात्रों के दृष्टिकोण का एक खोजपूर्ण अध्ययनरू इलाहाबाद शहर के विशेष संदर्भ** में, इंटरनेशनल जर्नल रिसर्च पब्लिकेशन, 07 (09), 186–194।
3. मुथुलक्ष्मी, ई.के. (2017): **भारतीय अर्थव्यवस्था पर विमुद्रीकरण के प्रभाव– मुद्दे और चुनौतियां,** मानविकी और सामाजिक विज्ञान के जर्नल, 34–38।
4. शाह, ए. वाई. (2017): **ग्रामीण भारत पर विमुद्रीकरण का प्रभाव**, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ साइंटिफिक एंड रिसर्च पब्लिकेशन्स, 7(3), 220–223।
5. शानभोग, जी. कुमार, ए.पी., भट, एस. और शेट्टीगर, सी. (2016): **500 और 1000 रुपये के नोटों के विमुद्रीकरण और विभिन्न क्षेत्रों और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव पर एक अध्ययन**, अर्थशास्त्र और सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान के अंतर्राष्ट्रीय जर्नल। 6(12), 274–284।
6. Veerakumar, K. (2017). **A Study on People Impact on Demonetization**] International Journal of

Interdisciplinary Research in Arts and Humanities.2(1)] 9-12.

7. MBA UNIVERSE. (2018), http://www.mbauniverse.com/groupdiscussion/topic/businesseconomy/demonetisatin.

8. Retrieved February 26, 2018, from http://www.mbauniverse.com YOUTH KI AWAAZ. (2018).

9. https://www.youthkiawaaz.com/2017/12/impact-of-demonetisation-on-the-indian-economy/

10. Retrieved February 27, 2018, from https://www.youthkiawaaz.com

11. INDIAN ECONOMY. (2018). https://www.indianeconomy.net/splclassroom/what-are-the-impacts-of-demonetisation-on-indian-economy/

12. Retrieved March 02, 2018, from https://www.indianeconomy.net

13. *(PDF) Impact of Demonetisation on Indian Economy: A Critical Study*. Available from: https://www.researchgate.net/publication/324952991_Impact_of_Demonetisation_on_Indian_Economy_A_Critical_Study [accessed Dec 26 2021].